

‘कांग्रेस ने सांप्रदायिक एजेंडा के तहत वंदे मातरम् के संक्षिप्त संस्करण को राष्ट्र गीत बनाया’

संसद में वंदे मातरम् पर बहस की शुरुआत करते हुए प्र.मंत्री मोदी ने कांग्रेस पर वंदे मातरम् का अपमान करने का आरोप लगाया

- जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 दिसम्बर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में ‘वंदे मातरम्’ की 150 वीं वर्षगांठ पर हुई चर्चा में कांग्रेस पर तीखा हमला किया और भारत के राष्ट्रीय गीत को विपक्षी पार्टी की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 50 साल पहले लगाए गए आपातकाल से जोड़ने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि उनके एक और पूर्ववर्ती, जवाहरलाल नेहरू, ने ‘वंदे मातरम्’ का विरोध करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना का अनुसरण किया था, क्योंकि यह “मुसलमानों को नाराज कर सकता था।” उन्होंने कहा, “जब ‘वंदे मातरम्’ को लिखे 100 वर्ष हुये थे, तब देश आपातकाल में फंसा हुआ था... जब यह अपने 100 वें वर्ष में था, तब संविधान का गला घोट दिया गया था।” प्रधानमंत्री ने कहा, “अब, 150 साल बाद, यह ‘वंदे मातरम्’ की महिमा

- प्र.मंत्री ने कहा, बकिम चंद्र ने जो वंदे मातरम् लिखा था उसके शुरुआती दो अंतरे राष्ट्र गीत में रखे गए, शेष 6 अंतरे हटा दिए गए, क्योंकि उसमें हिंदू देवियों, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का संदर्भ दिया गया था, यह कांग्रेस का सांप्रदायिक एजेंडा था।
- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 1875 में वंदे मातरम् की रचना हुई थी। अब इसकी 150वीं जयंती है. यह अच्छा अवसर है, इसकी महिमा बहाल करने का।

को बहाल करने का एक अच्छा अवसर है... जिसने हमें 1947 में स्वतंत्रता दिलाई थी।” उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1875 में लिखे गए इस गीत की सराहना की, और कहा कि यह जल्द ही स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक नारा बन गया था। “हमने हाल ही में अपने संविधान की 75 वीं वर्षगांठ मनाई। देश ने सरदार वल्लभभाई पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई। हम गुरु तेग बहादुर जी का 350वें शहीदी दिवस भी मना रहे हैं। अब हम ‘वंदे मातरम्’ के

के तहत इसका अनादर किया था और इसे इसके संक्षिप्त रूप में देश का राष्ट्रीय गीत बना दिया था। इस विवाद के केन्द्र में इसके छः अन्तरे हैं, जिनमें चट्टोपाध्याय ने हिन्दू देवी दुर्गा, कमला (या लक्ष्मी) और सरस्वती का संदर्भ दिया था, और इन्हें भारत की संरक्षक के रूप में प्रस्तुत किया था। 1937 में, कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष उस समय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ने राष्ट्रीय समारोहों में इसके केवल पहले दो अन्तरे (स्टैन्डा) गाने का निर्णय लिया था। इसका तर्क यह था कि हिन्दू देवियों के सीधे संदर्भ मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्यों द्वारा अच्छी तरह से नहीं लिए गए थे; इन्हें “बहिष्कार योग्य” माना गया था। प्रस्ताव में लिखा था: “सभी बातों पर विचार करते हुए, समिति यह सिफारिश करती है कि जब भी ‘वंदे मातरम्’ राष्ट्रीय समारोहों में गाया जाए, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

–मुर्शिदाबाद के बाद, ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा हुई

यू.पी. के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तीखी प्रतिक्रिया की कि मस्जिद बनाने पर कोई आपत्ति नहीं है, पर, अगर यह मस्जिद बाबर के नाम पर बनाई जाती है तो सख्त आपत्ति होगी।

- श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 दिसम्बर। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की एक प्रतिकृति बनाने की योजनाओं ने भाजपा के बीच भारी हलचल मचा दी है, यह विवाद अब और बढ़ता हुआ दिख रहा है, जब ‘तहरीक मुस्लिम शब्बन’ नामक एक समूह ने हैदराबाद के ग्रेटर इलाके में बाबरी मस्जिद स्मारक बनाने की योजना की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में, निर्लंबित तृणमूल विधायक हुमायूँ कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले में पहले मुगल सम्राट बाबर के नाम पर मस्जिद का शिलान्यास करने के अपने निर्णय से विवाद खड़ा कर दिया। इस विवाद पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई, जिन्होंने कहा कि भाजपा न केवल इस निर्माण का विरोध करेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित

- हैदराबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का एलान करने वाले तहरीक मुस्लिम शब्बन के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक ने इस पर कहा, “किसी को भी बाबर के नाम पर आशंकित नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहीं भी जिद्द नहीं कि अयोध्या मस्जिद के निर्माण में बाबर का कुछ पैसा लगा था। यह संभव है कि पुरानी बाबरी मस्जिद किसी स्थानीय व्यक्ति बाबर के नाम पर बनी हो। भाजपा व आरएसएस इस बात को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। बाबर का शासनकाल तो बहुत छोटा था।”

करेगी कि इसे जल्दी से तोड़ा जाए। “मस्जिद के निर्माण में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कोई इसे बाबर के नाम पर बनाता है, तो इसे मजबूत विरोध का सामना करना पड़ेगा।” पश्चिम बंगाल में अगले साल के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, और आस्था के मुद्दे पर भाजपा को यह मसला प.बंगाल में साम्प्रदायिक

सुनील शर्मा राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त



सुनील शर्मा

जयपुर, 8 दिसम्बर (कासं)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सोमवार को आदेश जारी कर सेवानिवृत्त आई.ए.एस. सुनील शर्मा को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने से 3 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, के लिए की गई है। ज्ञात रहे कि सुनील शर्मा इस साल अप्रैल में ही सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। शर्मा, वर्ष (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जापान में भारी भूकंप, सुनामी की चेतावनी

टोक्यो, 08 दिसंबर। जापान में सोमवार को भूकंप के भीषण झटके से कांप उठा। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई है। भूकंप के तुरंत बाद जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने सुनामी की चेतावनी जारी की है। इस कारण जापान के उत्तर-पश्चिमी तट पर तीन मीटर (10 फीट) ऊंची सुनामी आ

- रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई है।

सकती है। मछुआरों और छोटी बोट को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। भूकंप का केंद्र मिसावा शहर से लगभग 73 किलोमीटर उत्तर-पूर्व की ओर स्थित था, जिसकी गहराई लगभग 53 किलोमीटर मापी गई। यह उथले श्रेणी का भूकंप माना गया, जो आमतौर पर अधिक तीव्र झटकों का कारण बनता है। जापान प्रशांत, फिलीपीन सागर, यूरेशियन और उत्तर अमेरिकी प्लेटों के संगम पर स्थित है।

‘सरकार ने वंदे मातरम् पर बहस इसलिए रखी क्योंकि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं’

प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि सरकार हमें अतीत में उलझाए रखना चाहती है और वर्तमान व भविष्य पर बात नहीं करना चाहती

- डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 दिसम्बर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा ने आज लोकसभा में वंदे मातरम् पर हुई बहस के दौरान, प्रधानमंत्री और भाजपा पर तीखा लेकिन चुटीला वार किया और प्रधानमंत्री की नेहरू पर बार-बार की जाने वाली आलोचना पर कड़ा हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान जितना समय जेल में बिताया था, वह लगभग उतना ही है, जितना समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सर्वोच्च पद पर बिताया है। वे वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर हो रही विशेष चर्चा में बोल रही थीं। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को सुझाव दिया कि वे जवाहरलाल नेहरू के लिए की गई सारी आलोचनाओं और अपमानों की एक पूरी सूची बना लें।

- प्रियंका गांधी ने कहा, भारत के पहले प्रधानमंत्री पं. नेहरू ने कहा था, वंदे मातरम् पर विवाद साम्प्रदायिक ताकतों ने गढ़ा था।
- प्रियंका ने अपने तर्क के पक्ष में नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच लिखी गई चिट्ठियों का उल्लेख किया। गुरुदेव टैगोर ने लिखा था, जिन दो पदों का हमेशा गायन होता रहा है, वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें शेष गीत से अलग करने में कोई समस्या नहीं है और आज़ादी के आंदोलन में सभी इन दो पदों को ही गाते थे।
- टैगोर ने यह भी लिखा था कि इस गीत में बाद के जो पद हैं, उन्हें उस दौर के माहौल को देखते हुए सांप्रदायिक कहा जा सकता है।

प्रियंका गांधी ने आगे कहा, “देश सुन लेगा कि इंदिरा जी ने क्या किया,

राजीव जी ने क्या किया, वंशवादी राजनीति क्या है, नेहरू की क्या गलतियाँ थीं—आइए, इन सब पर बात कर लेते हैं और फिर इसे हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। फिर हम बेरोजगारी और महँगाई पर बात कर पाएँगे।” उनके इस बयान पर भी विपक्षी बेंचों ने जोरदार करतल - ध्वनि की। इससे पहले, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने वंदे मातरम् पर यह बहस अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए आयोजित की है। प्रियंका ने कहा, “यह बहस इसलिए करवाई जा सके, क्योंकि यह सरकार मौजूदा हालात की सच्चाई छिपाना चाहती है।”

वायनाड की सांसद ने यह भी सवाल उठाया कि संसद में वंदे मातरम् पर बहस की जरूरत ही क्या है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि यह गीत “देश के हर हिस्से में जीवित है और सम्मानित है।” उन्होंने कहा कि सरकार वंदे मातरम् पर चर्चा इसलिए चाहती है, क्योंकि जल्द ही बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। सरकार चाहती है कि हम अतीत में उलझे रहें, क्योंकि वह वर्तमान और भविष्य पर बात करना नहीं चाहती।” प्रियंका गांधी वाड़ा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस प्रकरण को गलत रूप में पेश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नेहरू, जो उनके परदादा और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ने वंदे मातरम् को लेकर हुए उस विवाद को “सांप्रदायिक ताकतों द्वारा खड़ा किया गया विवाद” कहा था। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वन रक्षक भर्ती का इनामी फरार आरोपी गुजरात से गिरफ्तार

जयपुर, 8 दिसम्बर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक मामले में पचास हजार रुपये के इनामी फरार आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी वन रक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक करने में अहम कड़ी है। गैंग के लोगों ने किन-किन लोगों को पेपर बेचा और कहाँ से लीक पेपर मिला, एसओजी की टीम यह पृष्ठताछ करने में जुटी है। एसओजी एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि ‘फरार आरोपी जबराम को

- एसओजी को आशा है कि इससे पूछताछ में यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि लोक पेपर कहाँ से हासिल किया तथा किस-किस को बेचा।

गुजरात से पकड़कर बांसवाड़ा लाया गया है और अब उससे पूछताछ की जाएगी।

एसओजी की पूछताछ के बाद सामने आएगा कि परीक्षा का पेपर लीक गैंग ने कहाँ से हासिल किया था और किन-किन लोगों को परीक्षा का पेपर बेचा गया था। आरोपी जबराराम सरकारी शिक्षक है और वनरक्षक भर्ती (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इंडिगो ही नहीं सभी भारतीय एयरलाइन्स बारूद के ढेर पर काम कर रही हैं

एक छोटी सी गलती, चिंगारी का काम करती है, पूरे सैक्टर को ढेर करने में

- एयरलाइन्स को टाइट बजट में काम करना होता है. हवाई जहाज़ के पेट्रोल पर भारी टैक्स है. हवाईअड्डों की क्षमता बहुत सीमित ही नहीं कम है. सैक्टर का संचालन करने वाले रेग्युलेटरी ढांचे का काम करने का तरीका अनिश्चित सा, लगभग मनमर्जी से चलने वाला लगता है।
- इंडिगो एयरलाइन्स के अनुभव ने यह जता ही दिया कि जब केवल एक्सपेंशन पर भारी जोर हो तो सिस्टम इतना नाजुक हो जाता है कि किसी भी दिक्कत से जूझकर, उसका सामना करके आगे बढ़ने की क्षमता उसमें नहीं रह जाती और तूफान तो दूर की बात है, हवा का झोंका ही ताश् के पत्ते के किले को ढहा देता है।
- सैक्टर को सुव्यवस्थित चलाए रखने के लिए गठित “रैग्युलेटरी सिस्टम” (नियंत्रक व्यवस्था) का रूख प्रतिक्रियात्मक है न कि दुर्घटना से पहले, दुर्घटना रोकने का इंतज़ाम करने वाला।
- इस सैक्टर का आधारभूत ढांचा- रनवे, पार्किंग स्थल, गेट्स, एरोब्रिज तथा ग्राउंड हैंडलिंग साधन इतने सीमित हैं कि किसी एक में कुछ गड़बड़ी हुई तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है।

‘इंडिगो संकट के झटके बिहार की सरकार में भी महसूस हुए

नीतीश की पार्टी जद (यू) ने पुरजोर ढंग से मांग उठाई की इंडिगो की “दिन दहाड़े डकैती” के खिलाफ सख्त और तुरंत कार्यवाही करे सरकार

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 दिसंबर। इंडिगो एयरलाइंस में चल रहे संकट ने सत्ताधारी एनडीए में अप्रत्याशित राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है, जिसमें गठबंधन सहयोगी हवाई उड़ानों की किराया वृद्धि और देशभर में व्याप्त संकट के चलते सार्वजनिक रूप से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इस स्थिति ने मोदी सरकार को असामान्य रूप से रक्षात्मक स्थिति में ला दिया है, क्योंकि प्रमुख सहयोगी तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग कर रहे हैं और निजी एयरलाइनों पर “दिनदहाड़े लूट” करने का आरोप लगा रहे हैं।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे एक वरिष्ठ जदयू नेता ने बुधवार को इंडिगो के दफ्तर के बाहर धरना देने की धमकी दी, एयरलाइन पर अफरातफरी के बीच यात्रियों का शोषण करने का आरोप लगाया। उनका यह

- जद (यू) नेता व एनडीए के जाने माने चेहरे के.सी. त्यागी ने एक व्यक्तिगत जानकारी देकर और हड़कंप मचा दिया कि “उन्हें अपनी बेटी के दिल्ली-मुंबई टिकट के लिए इकतालीस हजार का नाजायज़ भुगतान करना पड़ा। त्यागी ने एयरलाइन्स से यह राशि लौटाने की मांग की तथा केन्द्रीय सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की “डिमांड” उठाई।
- त्यागी के अनुसार, यह मार्केट प्राइसिंग” नहीं है, बल्कि संकट के नाम पर शोषण है।
- पहली बार सरकार को विरोध का सामना विपक्ष की ओर से ही नहीं, अपने सहयोगी पार्टी की तरफ से करना पड़ रहा है।

आक्रोश एनडीए के भीतर गहरी निराशा को दर्शाता है, जो, साक्षेदारों के अनुसार, नागरिक विमानन क्षेत्र में शासकीय और नियामक विफलता का परिणाम है। इस दबाव को और बढ़ाते हुए, वरिष्ठ जदयू नेता और एनडीए का प्रमुख

चेहरा के.सी. त्यागी ने सरकार को एक व्यक्तिगत खुलासा करके चौंका दिया कि उन्हें अपनी बेटी के दिल्ली-मुंबई टिकट के लिए 41,000 रुपये की भारी राशि का भुगतान करना पड़ा। इसे “पूर्णतया लूट” बताते हुए, त्यागी ने

एयरलाइन से तत्काल रिफंड की मांग की और केन्द्र से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। “यह बाजार मूल्य निर्धारण नहीं है। यह संकट के नाम पर शोषण है”, त्यागी ने पार्टी के सहयोगियों से कथित तौर पर कहा, यह संकेत देते हुए कि नाराजगी न तो प्रतीकात्मक है और न ही राजनीतिक रूप से मंचित। अंदरूनी सरकार सूत्र इस विवाद पर चुपपी साधे हुए हैं, जबकि इस घटना ने केन्द्र के संकट प्रबंधकों के लिए एक अजीब और असहज स्थिति उत्पन्न कर दी है, जो पहले ही विमानन क्षेत्र में एक प्रमुख निजी एयरलाइन पर अत्यधिक निर्भरता के कारण आलोचना का सामना कर रहे हैं। मोदी सरकार कई मोर्चों पर समस्याओं का सामना कर रही है, यात्रियों के गुस्से और किराए के उतार-चढ़ाव से लेकर नियामक निगरानी, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गोवा अग्निकांड के आरोपी थाइलैंड फरार

गोवा, 08 दिसंबर। गोला क्लब हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। गोवा अग्निकांड के आरोपी थाईलैंड भागने में कामयाब हो गए हैं। अब गोवा पुलिस ने सीबीआई के जरिए इंटरपोल से मदद मांगी है। जिस

- गोवा पुलिस ने यह जानकारी दी। दोनों आरोपी सौरभ और गौरव भाई हैं तथा उस बार के मालिक हैं, जहां हादसा हुआ।

दिन घटना हुई, उसी दिन आरोपियों ने मुंबई से फुकेट (थाईलैंड)की फ्लाइट पकड़ी और भारत से बाहर भाग गए। डीजोपी गोवा आलोक कुमार के अनुसार ये खबर निकलकर सामने आई है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से से जानकारी मिली कि दोनों मालिक आग लगने के तुरंत बाद 7 दिसंबर को सुबह 05.30 (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है। –कहावत

मिनिमम गवर्नेंस, नो गवर्नमेंट

प्रधानमंत्री मोदी ने जब 2०14 में प्रधानमंत्री का पद संभाला था तो यह घोषणा की थी कि वे “मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट” का सिद्धांत लागू करेंगे और इस दिशा में कार्य करेंगे। प्रारंभ के कुछ निमित्तों से ऐसा लगा कि सरकार उसी ओर चल रही है, किंतु जैसे–जैसे समय निकलता गया, यह नारा केवल नारा ही बनकर रह गया। वास्तव में सरकार की कार्यप्रणाली किसी और ही दिशा में चलने लगी। निजीकरण को बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगा, जिसमें कोई बुराई भी नहीं थी, किंतु इसके बेलगाम होने का क्या परिणाम हो सकता है, यह हाल ही के दिनों में कई स्थानों पर देखने में आया है।

गत सप्ताह में इंडिगो एयरलाइंस से यात्रा करने वाले यात्रियों को दुर्दशा एवं लाचारी के जो दृश्य, विभिन्न मीडिया माध्यमों पर दिखाए गए, चाहे वे टीवी चैनल हों, सोशल मीडिया हों अथवा प्रिंट मीडिया, बड़े हृदय विदारक थे। कई ऐसे बुजुर्ग थे जो घंटों, बिना दवा के एयरपोर्ट पर बैठे रहे, कई डॉक्टर सर्जरी करने नहीं पहुँच पाए, जिन मरीजों की किसी दूसरे शहर में सर्जरी होनी थी, वह नहीं हो पाई। कुछ मामलों में तो नव दंपति अपने खुद के रिसेप्शन में भी सम्मिलित नहीं हो पाए और उन्हें केवल वीडियो के माध्यम से सम्मिलित होना पड़ा। बिलखते बच्चे और रोती हुई आक्रोशित महिलाओं के दृश्य प्रतिदिन आ रहे हैं। फ्लाइट 2० घंटों के विलंब से जा रही थी। हजारों फ्लाइट्स कैसिल हो गईं। हजारों लोग परीक्षा और इंटरव्यू देने से वंचित रह गए। बहुत से लोगों को विदेशी की कर्मकिर्ता फ्लाइट छूट गई। इंडिगो के कर्मचारियों के पास केवल एक ही रटा रटया उत्तर था कि तकनीकी कारणों से विलंब हो रहा है, फ्लाइट रीशेड्यूल कर रहे हैं अथवा कैसिल हो रही है। भारत में नागरिक की स्थिति कितनी दयनीय हो गई है, यह इसी से पता लगता है कि कोई स्पष्ट उत्तर देने वाला नहीं था कि उनकी फ्लाइट गंतव्य के लिए कब और कितने बजे खाना होगी? जिन लोगों को अत्यावश्यक रूप से कहीं जाना था इसके लिए उन्हें वैकल्पिक फ्लाइट के टिकट, अन्य एयरलाइंस से मनमानी कीमत पर खरीदने पड़े। ऐसा देखा गया कि जिन दो शहरों के बीच में सामान्य टिकट की दर 7– 8000 रुपए थी, वहां के लिए 30000 से 1०0000 रुपए तक लोगों को मजबूरी में देने पड़े।

इंडिगो ने केवल यह कहकर अपने कर्तव्य को इतिश्री कर ली और यात्रियों पर ‘उपकार’ कर दिया कि वह यात्रियों को फ्लाइट रह होने पर पूरा किराया रिफंड करेगी। यह नहीं सोचा कि रिफंड तो 7०00 रुपए का होगा लेकिन नया टिकट 7००00 रुपए का होगा। यही स्थिति कुंभ मेले के समय भी हुई थी जब 5०00 के स्थान पर लोगों को 50000 रुपए तक देने पड़े थे।

यह सब होते हुए भी सरकार आंखें मूंद कर बैठी रही। उसने न तो एयर लाइन पर कोई ज़ुर्माना लगाया न यात्रियों को कोई मुआवजा देने के लिए इंडिगो को बाध्य किया। यह उल्लेखनीय है कि भारत के विमानन उद्योग में इंडिगो का हिस्सा लगभग 65 प्रतिशत है, अर्थात इसका एकाधिकार है। स्पष्ट है इंडिगो कंपनी निश्चित है कि डी जी सी ए या उड्डयन मंत्रालय उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेगा। यह अति आत्मविश्वास शायद इसलिए कि सितंबर, 2025 से प्रधानमंत्री के अत्यन्त करीबी नीति आयोग के पूर्व सी ई ओ, इंडिगो के निदेशक बन गए हैं। कहा भी गया है, “सैंया भए कोतवाल तो डर काहे का”? एयरलाइंस पर कोई कार्रवाई न करने को जनता के हितों की अनेखी करना ही कहा जाएगा। इंडिगो ने न तो यात्रियों के लिए होटल की व्यवस्था की न खाने की। स्थिति तो यह है कि विगड्ड गई कि एक बुजुर्ग द्वारा जब अपनी बेटी के लिए एयरलाइंस स्टॉफ से सैनिटरी नेपकिन की मांग की गई तो वह तक उपलब्ध नहीं कराया गया। लोग 5 घंटे से लेकर 2० घंटे तक अनिश्चिताता की हालत में विभिन्न एयरपोर्ट पर बैठे रहे। एयरपोर्ट पर भीड़ की स्थिति किसी शहर के वस अट्टे से भी खराब हो गई थी।

आज प्रत्येक नागरिक यह प्रश्न पृष्ठ रहा है कि क्या सरकार का ‘मैक्सिमम गवर्नेंस’ का यही तात्पर्य है कि यात्रियों को निजी कंपनियों की दया पर छोड़ दिया जाए? उल्लेखनीय है कि इंडिगो का मुनाफा केवल वित्तीय वर्ष 2०24 में ही आठ हजार करोड रुपए से अधिक था। क्या सरकार इस कंपनी को अडेस नहीं दे सकती है कि वह पीडित यात्रियों को कम से कम एक लाख रुपए का मुआवजा दे? नागरिक उड्डयन मंत्रालय जिसके पास विभिन्न एयरलाइन एवं हवाई यात्राओं को नियमित करने की जिम्मेदारी है, उसने इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब तक इस एयरलाइंस पर ज़ुर्माना लगाने की भी कोई जानकारी नहीं है।

मीडिया में प्राप्त जानकारी से पता लग रहा है कि विभिन्न सुरक्षा संबंधी मानकों को ध्यान में रखते हुए और पायलटों के उड़ान के घंटे निर्धारित करने के कारण इंडिगो के लिए फ्लाइट संचालन करना असंभव था। फिर भी इंडिगो को अपनी फ्लाइट्स की संख्या 14०00 से बढ़ाकर 15०00 करने की अनुमति दी है। इन सब का परिणाम यह हुआ कि इंडिगो के पास पायलटों की संख्या अत्यंत कम हो गई। बदली परिस्थितियों में, इंडिगो ने आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पायलटों की समय पर भर्ती नहीं की। इसका असर फ्लाइट के संचालन पर पड़ना हो था। यह आश्चर्य की बात है कि अब सरकार ने पायलटों के उड़ान के घंटे नियमित करने वाला अपना आदेश इंडिगो कंपनी के लिए 1० फरवरी तक स्थाित कर दिया है। ऐसा करके क्या सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा को ताक पर नहीं रख दिया है? प्रधानमंत्री जी ने नारा तो “मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट” का दिया था लेकिन निजी कंपनियों को जिस प्रकार से मनमानी करने की खुली छूट दे दी गई है, उसे तो ‘मैक्सिमम गवर्नेंस’ के स्थान पर ‘नो गवर्नेंस’ ही कह सकते हैं।

सरकार की अनुपस्थिति लगभग हर उस क्षेत्र में अनुभव की जा रही है जिससे नागरिक का जीवन प्रभावित होता है। वाहनों की संख्या में अनाप-शनाप वृद्धि से शहरों में पार्किंग का कोई स्थान नहीं बचा है और इसलिए सड़कों पर वाहन बेतरतीब खड़े रहते हैं, जिसके कारण प्रतिदिन सड़क हादसों में लोग पर रहे हैं। अतिरिक्त और भवन निर्माण के नियमों की अखंडलता एक सामान्य बात हो गई है। जयपुर के मालवीय नगर में एक निर्माणधीन चार मंजिला भवन झुकने लगा और जनजीवन के लिए खतरा बन गया तो पता चला कि यह बिना अनुमति के बन रहा था। कैसी सरकार और कैसा शासन?

चलती बसों में आग लगने के कारण यात्रियों की मृत्यु होना, अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के कारण हुई आग से मरीजों की मौत होना, यही सिद्ध करते हैं कि सरकार के लिए आम नागरिक के जीवन का कोई महत्व नहीं रह गया है। जब मैं यह संपादकीय लिख ही रहा हूँ तभी गोवा के नाइट क्लब में भयंकर आग लगने की खबर आई है। इसमें 25 लोग दम घुटने से मर गए क्योंकि उनके और जाने का एक ही दरवाजा था। स्पष्ट है, न सरकार को न शासन।

जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है उसके अधिकारियों का काम केवल व्यापारियों और आम जनता से अनधिकृत रूप से वसूली करना रह गया है। जनता का हित सरकार के लिए सबसे अंतिम प्राथमिकता बनकर रह गया है। जिस प्रकार से अस्पतालों में मुख्यमंत्री आरक्षण योजना लागू होने के बाद भी गरीब लोग अस्पताल में धक्के खा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। लोकतांत्रिक कल्याणकारी सरकार का पहला दायित्व यही होता है कि वह जनता के हित को सर्वोपरि रखे, लेकिन जिस प्रकार के घटनाक्रम हम आजकल देख रहे हैं, उसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि सरकार के लिए बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों का हित संरक्षण ही एकमात्र काम रह गया है। साधारण जनता को निजी कंपनियों के हवाले छोड़ दिया गया है। मेडिकल की पढाई करने वाले एक–एक छात्र से साल का एक करोड रुपया लिया जा रहा है। ऐसा करके क्या कभी कोई साधारण परिवार का व्यक्ति वर्तमान शासन व्यवस्था में एमबीबीएस या एम डी करने की सोच भी सकता है?

विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों अथवा अन्य सेवाओं के कर्मचारियों/ अधिकारियों को सुशासन पर प्रशिक्षण दिए जाने के बावजूद यदि हम गुड गवर्नेंस के बजाय ‘नो गवर्नेंस’ की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो यह चिंता की बात है। इस प्रकार की स्थिति में, जिनके पास अकूत धनराशि है या जो प्रभावशाली हैं, वे तो किसी भी प्रकार से अपना काम निश्चित लेंगे लेकिन साधारण नागरिक के पास तो प्रताड़ित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। उदाहरण के लिए, हाल ही में किए जा रहे एस आई आर में लगभग सभी सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढाई, जो वैसे ही खस्ता हाल है, अब बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। सरकार के संरक्षण की आवश्यकता ही साधारण परिवार को सर्वाधिक होती है और दुर्भाग्य से वही शोषण का शिकार हो रहा है। सरकार अपने मूल दायित्व को तिलांजलि देकर केवल पूंजीपतियों के हित संरक्षण को उठी रहेगी तो वही स्थिति होगी जो अभी इंडिगो के प्रकरण में हुई है।

आज नागरिक प्रश्न पृष्ठ रहा है कि सरकार को उससे विभिन्न नामों से टैक्स वसूल करती है उससे उसे लाभ क्या हो रहा है ? सरकार न तो उसे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है न ही उसे निजी क्षेत्र के हाथों शोषित होने से बचा पा रही है। उसके बच्चे यदि पढाई नहीं कर सके, रहने के लिए अपना छोटा सा घर नहीं बना सके, अपने लिए कोई रोजगार नहीं ढूँढ सके, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लोक होते चले जाएं तो उसे हम लोक कल्याणकारी राज्य का नागरिक कह पाएंगे ? सरकार को चाहिए था कि तेजी से निजीकरण करते समय एक प्रभावी नियामक व्यवस्था स्थापित करती। पैसे की ताकत के आगे सरकार के मंत्री और अधिकारी या तो लाचार हैं या अपने स्वार्थ के कारण उनके समक्ष नतमस्तक हो गए हैं। यह भी पता चला है कि इंडिगो कंपनी के मालिक राहुल भाटिया ने सप्ताधाारी दल को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 20 करोड रुपए दिए थे। यदि ऐसा नहीं है तो फिर अब तक नागरिक उड्डयन मंत्री और महानिदेशक डी जी सी ए को क्यों नहीं हटया गया है ?

साधारण जनता मिलावटी दूध पीने, मिलावटी सब्जियां, फल एवं खाद्य पदार्थ खाने और जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। वास्तव में सरकार होती तो मिलावट करने वालों को अब तक सजा मिल चुकी होती। न किसी को जेल हुई न किसी को गिरफ्तार किया गया।

मेरे जैसे साधारण नागरिक को तो केवल एक ही अपेक्षा है कि सरकार प्रभावी रूप से नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करे और नियंत्रण व्यवस्था में ऐसे लोगों को लगाए जो ईमानदारी से अपना काम करें, ताकि निजी संस्थाएं भी बनी रहें और किसी का शोषण भी व्यवस्था में न हो।

इंडिगो की हाल की घटनाक्रम से तो यह लगता है कि सरकार पूरे प्रकरण में अनुपस्थित ही रही है। अनुपस्थित सरकार जनता का भला नहीं कर सकती। जनता चाहती है कि सरकार उसके हित में काम करे। हम तो केवल आशा ही रख सकते हैं कि सरकार अब भी जागे और सुशासन नहीं तो कम से कम शासन तो उपलब्ध कराए। दुर्भाग्य से न्यायपालिका भी सरकार की निष्क्रियता का संज्ञान नहीं ले रही है और न सरकार को बाध्य कर रही है कि वह एक प्रभावी कार्यपालिका की भूमिका संविधान के अंतर्गत निभाए।

फिलहाल तो ऐसा लगता कि प्रधानमंत्री का “मैक्सिमम गवर्नेंस” का दावा ‘नो गवर्नेंस’ में परिवर्तित हो गया है।

–अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र भागवत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



डॉ. लोकेश चंद्र शर्मा

राजस्थान विधानसभा म राष्ट्रीय गात वंदे मातरम् को समर्पित विशिष्ट, शोधपरक और आधुनिक स्वरूप वाली दीर्घा में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, स्वाधीनता के सांस्कृतिक प्रतीकों और राष्ट्रभक्ति की सामूहिक चैतना के ऐतिहासिक तथ्यों को नए स्वरूप में प्रस्तुत किया है। भारतीय लोकतंत्र की आत्मा से संवाद करती इस

पहल से देश की विधान सभाओं में राजस्थान विधान सभा इस ऐतिहासिक उपलब्धि से विशिष्ट बन गई है। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी की इस गौरवमयी सोच के साकार होने से विधान सभा का पवित्र परिस्र शौर्य के भाव से आलोकित हो गया है। श्री देवनानी ने विधान सभा में भारतीय संविधान के 22 भागों के प्रारम्भ में प्रकाशित चित्रों की पृष्ठभूमि को समझाने के लिए संविधान दीर्घा और कारगिल वीरगणनाओं को समर्पित शौर्य वाटिका का भी निर्माण कराया है।

राजस्थान विधान सभा देश की पहली विधान सभा जहां वंदे मातरम् दीर्घा- देश की विधानसभाओं में राजस्थान



प्रो. वीर बहादुर सिंह

राजस्थान सरकार ने प्रदेश में पांच कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की, ये संस्थान, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और जोबनेर स्थानों पर संचालित हैं। ये सभी विश्वविद्यालय विधान सभा में उपयुक्त विधान पेश कर और गजब में नोटिफिकेशन उपरांत स्थापित किये गए हैं। सभी के विधान भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली के मॉडल एकट अनुसरु बनाये गए हैं। एक प्रकार से ये एन्ट और स्टूट्रेस सम्बन्धित विश्वविद्यालय के लिए संविधान का उद्देश्य पूरा करते हैं जिनके प्रोविशंस के अनुसार विश्वविद्यालय अपने सभी क्रिया कलापों को अंजाम देते हैं।

इसके ही प्रावधानों के अंतर्गत कुछ बड़ी समितियाँ गठित होती हैं जिनमें प्रबंध मंडल सर्वोच्च औरअकादमिक काँसिल प्रमुख हैं। फिर विधान के ही अंतर्गत बोर्ड ऑफ स्टडीज अथवा फैकल्टी होती है। एक फैकल्टी एक संकाय के सभी अकादमिक और नॉन अकादमिक कार्य देखती है। वर्तमान स्थिति में कृषि संकाय, कृषि अभियांत्रिकी संकाय, होम साइंस संकाय, डेरी व् फूड टेक्नोलॉजी संकाय और फिशरीज लिमनोलोजी संकाय और बागवानी व् फारेस्ट्री संकाय इन संस्थानों में गठित किये हुए हैं। प्रत्येक मुख्य संकाय का एक महाविद्यालय है जैसे कृषि महाविद्यालय, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, होम साइंस महाविद्यालय, डेरी व् खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय आदि जहाँ शिक्षा और अभिस्नातक स्तरों को शिक्षा देने का प्रावधान है सभी महाविध्यालयों में अनेक विषय अनुसार विभाग होते हैं।जिनमें प्रत्येक

इसके ही प्रावधानों के अंतर्गत कुछ बड़ी समितियाँ गठित होती हैं जिनमें प्रबंध मंडल सर्वोच्च औरअकादमिक काँसिल प्रमुख हैं। फिर विधान के ही अंतर्गत बोर्ड ऑफ स्टडीज अथवा फैकल्टी होती है। एक फैकल्टी एक संकाय के सभी अकादमिक और नॉन अकादमिक कार्य देखती है। वर्तमान स्थिति में कृषि संकाय, कृषि अभियांत्रिकी संकाय, होम साइंस संकाय, डेरी व् फूड टेक्नोलॉजी संकाय और फिशरीज लिमनोलोजी संकाय और बागवानी व् फारेस्ट्री संकाय इन संस्थानों में गठित किये हुए हैं। प्रत्येक मुख्य संकाय का एक महाविद्यालय है जैसे कृषि महाविद्यालय, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, होम साइंस महाविद्यालय, डेरी व् खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय आदि जहाँ शिक्षा और अभिस्नातक स्तरों को शिक्षा देने का प्रावधान है सभी महाविध्यालयों में अनेक विषय अनुसार विभाग होते हैं।जिनमें प्रत्येक

इसके ही प्रावधानों के अंतर्गत कुछ बड़ी समितियाँ गठित होती हैं जिनमें प्रबंध मंडल सर्वोच्च औरअकादमिक काँसिल प्रमुख हैं। फिर विधान के ही अंतर्गत बोर्ड ऑफ स्टडीज अथवा फैकल्टी होती है। एक फैकल्टी एक संकाय के सभी अकादमिक और नॉन अकादमिक कार्य देखती है। वर्तमान स्थिति में कृषि संकाय, कृषि अभियांत्रिकी संकाय, होम साइंस संकाय, डेरी व् फूड टेक्नोलॉजी संकाय और फिशरीज लिमनोलोजी संकाय और बागवानी व् फारेस्ट्री संकाय इन संस्थानों में गठित किये हुए हैं। प्रत्येक मुख्य संकाय का एक महाविद्यालय है जैसे कृषि महाविद्यालय, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, होम साइंस महाविद्यालय, डेरी व् खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय आदि जहाँ शिक्षा और अभिस्नातक स्तरों को शिक्षा देने का प्रावधान है सभी महाविध्यालयों में अनेक विषय अनुसार विभाग होते हैं।जिनमें प्रत्येक

राशिफल मंगलवार 9 दिसम्बर, 2025	
	
पौष मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2०82, आश्लेषा नक्षत्र रात्रि 2:23 तक, ऐन्द्रन योग दिन 2:23 तक, तैतिल करण दिन 2:29 तक, चन्द्रमा रात्रि 2:23	
पंडित अनिल शर्मा	से सिंह राशि में संचार करेगा।
ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-कर्क मंगल-धनु, बुध-वृश्चिक, गुरु-मिथुन, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।	
आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि 2:23 तक है। रवियोग और कुमार योग रात्रि 2:23 से आरम्भ होगा।	
श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:44 से 11:०1 तक, लाभ-अमृत 11:31 से 1:37 तक, शुभ 2:54 से 4:12 तक।	
राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 7:08, सूर्यास्त 5:29 तक	

विधानसभा अब उन विरल संस्थानों में शामिल हो गई है जहाँ वंदे मातरम् पर आधारित एक पूर्ण शोधपरक गैलरी का निर्माण हुआ है। राष्ट्र गीत के एक सौ पचास वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में तैयार इस दीर्घा में 37 पैनोंल के माध्यम से वंदे मातरम् की रचना, इतिहास, संदर्भ और स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भूमिका को क्रमबद्ध रूप से सजाया गया है। वंदे मातरम्, मातृभूमि के प्रति समर्पण, औपनिवेशिक दमन के विरुद्ध प्रतिरोध और स्वाधीनता की सामूहिक चेतना का स्वरूप है। स्वदेशी आंदोलन के दौर में यह गीत जनसभाओं और आंदोलनों का प्रेरक केंद्र बनकर राष्ट्रीय भावता को संगठित करता रहा और उसी चिरंतन स्वरूप को यह दीर्घा आधुनिक माध्यमों में पुनर्जीवित कर रही है।

नए विमर्श और आधुनिकता के साथ आमजन को समर्पित- राजस्थान विधानसभा परिसर स्थित राजनैतिक आख्यान संग्रहालय में यह नई दीर्घा स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को नए विमर्श और आधुनिक प्रस्तुति के साथ आमजन तक पहुँचाती है। वंदे मातरम् के भावपूर्ण संगीत, दुर्लभ दस्तावेजों, वीडियो सामग्री और उस युग के सांस्कृतिक-राजनैतिक परिवेश का सजीव प्रदर्शन आगतुकों को उस समय की अनुभूति से जोड़ता है। मातृभूमि के प्रति प्रेम, कर्तव्य और संविधान के प्रति निष्ठा को इस दीर्घा का मूल केंद्र माना गया है, जो इसे मात्र प्रदर्शनी नहीं बल्कि प्रेरणा का स्थायी स्रोत बनाता है।

जीवंत ज्ञान केन्द्र- 1875 में अक्षय नवमी के दिन बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा मुर्शिदाबाद के लालगोला में रचे गए मूल गीत की

पांडुलिपि, संस्कृतनिष्ठ बंगाली पाठ, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े दुर्लभ फोटोग्राफ, क्रांतिकारियों के संस्मरण, पत्र, भाषण और तत्कालीन सांस्कृतिक वातावरण की झलक इस दीर्घा को विशेष बनाती है। युवा वर्ग, शोधार्थियों और इतिहास में रुचि रखने वाले नागरिकों के लिए यह दीर्घा एक जीवंत ज्ञान केन्द्र के रूप में उभर रही है। राष्ट्रीय चेतना को आलोकित करने वाली राजस्थान विधान सभा ने नई पीढ़ी के लिए कर्तव्यों और अधिकारों के संतुलन के साथ राष्ट्र-प्रथम की भावना को सर्वोपरि बनाये रखने का वातावरण निर्मित किया है।

स्पीकर श्री वासुदेव देवनानी की इस पूरी पहल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि राजस्थान विधानसभा ने इतिहास को स्थिर रूप में नहीं, बल्कि जीवंत एवं सं

हादसे में महिला सहित तीन लोगों की मौत

निजी बस बाइक को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलटी खाई



हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना इलाके के मानकसर में सोमवार सुबह एक निजी बस पलटने के बाद मौके पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई।

बग्गा सिंह (28) की मौके पर ही मौत हो गई। बस पलटने से बस में सवार गंभीर रूप से घायल हनुमानगढ़ टाउन की नई आबादी निवासी महिला कमलदीप कौर (35) ने भी दम तोड़ दिया। वहीं रामपुर (यूपी) निवासी अनवर अली (45), श्रीकरणपुर (बाई 9) निवासी (62), सुरेशिया निवासी सुरेंद्र कुमार (45), सुरेशिया आनंद पांडे (40), कणवाली रावतसर

■ **बस में सवार घायल यात्रियों को संगरिया पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया।**

निवासी कालुराम (47) (जो वर्तमान में संगरिया में हेड कांस्टेबल हैं) और श्रीगंगानगर की पुष्पा (40) घायल हो गए। इनमें से तीन घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। एसपी हरी शंकर ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि बाइक सवार युवक नगराना गांव के रहने वाले थे और घटनास्थल के पास एक होटल से निकले थे।पुलिस ने बस को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत

जोधपुर पॉक्सो केस में पीड़िता की ओर से दायर स्पेशल लीव पिटीशन खारिज

■ **पीड़िता ने 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की थी। इसमें राजस्थान राज्य और आसाराम बापू उर्फ आशुमल को प्रतिवादी बनाया**

लॉ कैटेगरी के तहत बच्चों के खिलाफ अपराध व पॉक्सो एक्ट 2012 की श्रेणी में दर्ज किया गया। सोमवार को सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। आसाराम बापू को जोधपुर केस में राजस्थान हाईकोर्ट से 29 अक्टूबर को 6 महीने की अंतरिम जमानत मिली थी। उसी दिन पीड़िता

लिफ आवेदन किए गए थे।इसके बाद पीड़िता की ओर से यह स्पेशल लीव पिटीशन दायर होकर 8 दिसंबर को सूचीबद्ध होने से कई दिनों पहले ही आसाराम बापू ने 3 नवंबर को एडवोकेट निशत बिश्नोई के माध्यम से कैबिनेट दाखिल कर दी थी, जो 24 नवंबर को इस मामले से लिंक हुई। ताकि बिना सुने कोई एकतरफा आदेश न हो सके। आज यह मामला सुप्रीम कोर्ट में बेल मैटर्स श्रेणी में लिस्ट होकर सुना गया, जहां पीड़िता की ओर से एडवोकेट अल्लोजे के. जोसेफ और आसाराम बापू के वकील पेश हुए।

फैक्ट्री में आग से नुकसान

भीलवाड़ा। सोमवार तड़के स्वरूपगंज स्थित रीको ग्रोथ सेंटर की नीता एंटरप्राइजेज गता फैक्ट्री में अचानक लगी भीषण आग ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। घने धुएं के गुबार ने कुछ ही मिनटों में फैक्ट्री परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। अल सुबह काम पर मौजूद मजदूरों ने स्थिति बिगड़ती देख तुरंत हमीरागढ़ थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थानाप्रभारी सुनील बेड़ा मौके पर पहुंचे और हालात गंभीर देखकर तत्काल अग्निशमन विभाग को बुलाया। दमकल वाहनों ने पहुंचकर करीब डेढ़ घंटे की कड़ी शेषकतत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस व अग्निशमन दल ने समय रहते आग की लपटों को दूसरे शेड तक फैलने से रोका।

हथियारों के साथ 50 हजार के इनामी सहित दो बदमाश पकड़े

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर कमिश्नरेट की महामंदिर पुलिस ने अवैध हथियारों को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने उदयपुर के हिस्ट्रीशीटर को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया है। इसमें एक बदमाश पचास हजार रुपए का इनामी है। आरोपी एक हिस्ट्रीशीटर की मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे। आरोपियों के कब्जे से तीन पिस्टल, दो कारतूस और एक क्रेटा कार भी जब्त की गई है। पुलिस अब उनसे हथियारों को लेकर पूछताछ कर रही है।

पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश ने बताया कि कमिश्नरेट पुलिस संगठित अपराधियों को चिन्हित करके कार्रवाई कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधिक तत्व यहां घूम रहे हैं। डीसीपी (पूर्व) पीडी निर्या की मॉनिटरिंग में इस सूचना को बीट कांस्टेबल प्रकाश ने डेवलप किया। इसके आधार पर पचास हजार के इनामी बदमाश उदयपुर निवासी हिस्ट्रीशीटर नरेश वाल्मीकि और जैसलमेर निवासी अमन वाल्मीकि को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से तीन पिस्टल और

- **तीन पिस्टल व दो कारतूस बरामद**
- **क्रेटा कार जब्त, हिस्ट्रीशीटर को मारने के लिए कर रहे थे प्लानिंग**

दो कारतूस बरामद हुए। आरोपी नरेश के खिलाफ अलग-अलग थानों में करीब 37 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं अमन के खिलाफ छह मुकदमे दर्ज हैं। इनके खिलाफ 111 की धारा लगाई गई है। जो संगठित अपराधियों के खिलाफ लगाई जाती है। दोनों को भदवासिया इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नरेश के खिलाफ उदयपुर पुलिस ने 50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। आरोपी इसके चलते फरार चल रहा था। आरोपी आने वाले समय में उदयपुर के ही हाईकोर अपराधी प्रवीण कसेटा की हत्या की साजिश रच रहा था। प्रवीण अंबामाता थाने का हिस्ट्रीशीटर है।

बिजली के तार गिरने से किसान की मौत

जोधपुर, (कासं)। देवू थाना क्षेत्र के पुनियाँ की ढाणी गोविंदपुरा गांव में बिजली के तार गिरने से एक किसान की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से झुलस गया। यह घटना 11 हजार केवी की बिजली लाइन के जर्जर पोल गिरने के कारण हुई। जानकारी के अनुसार 11 हजार केवी की विद्युत लाइन पर लगे सात जर्जर पोल अचानक गिर गए। इससे 11 केवी के तार पास से गुजर रही एलटी लाइन पर गिरे, जिससे एक ट्रांसफार्मर भी नीचे आ गया। एलटी लाइन में विद्युत आपूर्ति चालू होने के कारण दो किसान इसकी चपेट में आ गए। हादसे में खेताराम मेघवाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, चेनाराम गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे देवू अस्पताल से जोधपुर रेफर किया गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि देवू डिस्कॉम को इन जर्जर बिजली के पोलों के बारे में पहले ही सूचित किया गया था। ग्रामीणों ने चेतावनी दी थी कि ये पोल कभी भी किसी की जान ले सकते हैं, लेकिन डिस्कॉम के अधिकारियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।

मुख्यमंत्री ने राजस्व से संबंधित विभागों की समीक्षा की

राज्य के सर्वांगीण विकास में राजस्व की भूमिका अहम, वृद्धि के लिए बनाएं लक्ष्य आधारित कार्य योजना

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास और सभी वर्गों के कल्याण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में विभिन्न विकास परियोजनाएं और जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने और जनकल्याणकारी योजनाओं के निर्बाध संचालन में राजस्व अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी समर्पित होकर कार्य करें। शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आबकारी, परिवहन, कॉमर्शियल टैक्स तथा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में 1 लाख 69 हजार 627 करोड़ रुपये के राजस्व अर्जन का लक्ष्य रखा गया था। इसे हासिल करने के क्रम में नवम्बर माह तक कुल 84 हजार 746



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की ।

करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आगामी तिमाही में राजस्व वृद्धि के लिए लक्ष्य आधारित कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। जीएसटी की दरों में कमी का लाभ उपभोक्ता को मिलना हो सुनिश्चित। शर्मा ने कॉमर्शियल टैक्स विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा किए गए जीएसटी

सुधारों से देश और प्रदेश के आमजन को काफी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जीएसटी की दरों में की गई कमी का सीधा लाभ उपभोक्ता तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने फर्जी करदातों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि कर चोरी रोकने और पारदर्शी कर व्यवस्था लागू करने के लिए सख्त निगरानी तंत्र

विकसित किया जाए। सार्वजनिक परिवहन हेतु नई बसों के हो परामित जारी मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक परिवहन हेतु नई बसों के अधिक से अधिक परामित जारी किए जाएं जिससे आमजन को आवागमन में सुविधा होने के साथ ही, राज्य सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति हो।

‘विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाये’

जयपुर । ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने निर्देश दिए हैं कि ब्लॉक ऑवर सप्लाई को मंटेन कर रबी सीजन में कृषि एवं अन्य उपभोक्ताओं को व्यवधान रहित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही सप्लाई को प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए मुख्यालय से निचले स्तर तक अधिकारी भेजे जाएं, जो कि ट्रिपिंग वाले गिड सब स्टेशनों तथा फीडर को चिन्हित कर उनमें लोड प्रबंधन की बेहतर प्लानिंग करें। नागर रबी सीजन में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्थाओं की मालवार को विद्युत भवन में समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान निर्देश दिए कि पीक ऑवर्स को डिमांड को पूरा करने के लिए बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। साथ ही प्रसारण निगम के स्तर पर भी बड़े हुए लोड के अनुरूप पावर ट्रांसफार्मर्स की क्षमता वृद्धि के उपाय अभी से कर लिए जाएं। बैठक में प्रमुख शासन सचिव (ऊर्जा) अजिताभ शर्मा ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं तथा आरडीएसएस के अन्तर्गत कृषि एवं गैर कृषि फीडर सेग्रेशन कार्य को गति देने के निर्देश दिए। चेयरमैन डिस्कॉम्स आरती डोगरा ने मांग एवं इसके अनुरूप वितरण निगमों द्वारा की जा रही आपूर्ति की जानकारी दी। बैठक में ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध निदेशक ओम कसेरा तथा उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक देवेन्द्र श्रृंगी ने विद्युत उपलब्धता के बारे में बताया।

दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जाने वाली 6 फ्लाइट कैसिल

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस का शेड्यूल लगातार गड़बड़ाया हुआ है। इंडिगो की आज छह फ्लाइट कैसिल की गई है। ये फ्लाइट्स दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद के लिए जोधपुर से जाने वाली थीं। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक जोधपुर से तीन फ्लाइट हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली शहरों से आती हैं। यहां से वापस इन शहरों के लिए जाती है।

इससे पहले रविवार को भी एयरपोर्ट से चार आने वाली और जाने वाली फ्लाइट को कैसिल किया गया था। हालांकि यहां पर रविवार को एयरपोर्ट पर फ्लाइट का संचालन नियमित हो गया था।

बीकानेर मंडी से हर रोज करीब 40 लाख बोरी मूंगफली गुजरात के व्यापारी खरीद रहे

- **गुजरात में बारिश की वजह से खराबा हुआ**
- **यूरोप और थाईलैंड तक होती है सप्लाई**

बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से खेतों में काफी पानी भर गया था। जमीन पथरीली होने के कारण वहां पानी फसल के ऊपर ही रहा, जिससे फसल खराब हुआ। ऐसे में इस बार दाना काफी छोटा और गीला निकला। लेकिन, उसकी तुलना में इस बार बीकानेर में गुजरात जैसी फसल हुई है। यहां इस इस बार दाना बड़ा और सुखा है। ऐसे में वहां के प्रोसेसिंग यूनिट और व्यापारियों में राजस्थान में होने वाली मूंगफली की डिमांड में अचानक बढ़ोतरी आई है। बीकानेर मंडी में रोजाना डेढ़ लाख

बोरी पहुंच रही है। कृषि मंडी के अधिकारियों के अनुसार इस बार 2 करोड़ क्विंटल बोरी इस बार बीकानेर की मंडी में आएगी।

गुजरात में इतनी डिमांड बढ़ चुकी है कि रोजाना बीकानेर मंडी से हर रोज करीब 40 लाख बोरी गुजरात के व्यापारी खरीद रहे हैं। वहीं पिछले पांच वर्षों में बीकानेर में मूंगफली का उत्पादन में लगातार बढ़ ता जा रहा है। इसका अंकड़ा देखे तो लगातार दूसरी बार सबसे ज्यादा 8 लाख 70 हजार मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। ये ही कारण है कि इस बार भी बीकानेर की मंडी पूरी तरह मूंगफली से अटी पड़ी है। हर रोज डेढ़ लाख बोरी मंडी पहुंच रही है। मूंगफली की बढ़ती डिमांड की वजह से इस बार भाव भी बढ़े है। पिछली साल की तुलना में प्रति बिन्टल 500 रुपए का मुनाफा हो रहा है। इस बार मूंगफली 5500 से 6500 रुपए क्विंटल के आस-पास बिक रही है।

तीन दोषियों को कारावास

कोटा । अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी के करीब साढ़े पांच वर्ष पुराने मामले में एनडीपीएस न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी के तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए दस-दस वर्ष के कोर कारावास साथ ही 1,00,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निम्बय ने बताया कि 18 जनवरी 2020 को थानाधिकारी थाना कुन्हाड़ी कोटा शहर ने नाकाबंदी के दौरान एक कार को डिटेन किया, जिसमें तीन जने बैठे हुए थे। कार में पीछे की सीट पर बैड़े हुए दोनो शख्सों के बीच में एक काले रंग का बैग रखा हुआ था। पुलिस टीम ने संदेह होने पर बैग की तलाशी ली तो बैग में से अवैध मादक पदार्थ 21 किलो गांजा बरामद किया।

 राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड	
	
ई-निविदा सूचना	दिनांक - 03/12/2025
निविदा संख्या एवं तिथि	कार्य का विवरण
F/9(141/C2/2025)-18 2025-18 Dated 03.12.2025 UBN No. MML2526GL0B00113	कसरनाक मालासुख लिमिटेड माईन्स गांव-मालासुख एहलीली-जायल नागर में एक 11 / *3 केबी न्यूटल घाटडिग रिफ़ायर (एनडीआर) की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण (निविदा दस्तावेजों में एन्क्लचर्ड सरी)। अनुमानित मूल्य (₹) 10.40 लाख, परोक्ष राशि (₹) ~ 20,800 /- , निविदा राशि ~ 1180 /- , अक्षरमालापीपी को एस टी. राशि। ई-निविदा अधिकार मुक्त कराने 500/- का डी.डी. जो कि एम.डी., आर.आई.एस.एल., जयपुर के नाम देना हो ।
उपरोक्त निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाईट www.rsmm.com अथवा www.sppp.raajasthan.gov.in अथवा प्रबंधक (सांख्यिकी-अनुबंध) से उपरोक्त पते पर सम्पर्क करें। <i>हल.हल/डी./25/15271</i>	www.rsmm.com अथवा www.sppp.raajasthan.gov.in पर सम्पर्क करें। <i>अनु.मालासुख (का.एच.प्र.)</i>

 OFFICE OF MEMBER SECRETARY, RAJASTHAN	
MEDICARE RELIEF SOCIETY	
SUPER SPECIALITY HOSPITAL, UDAIPUR	
No. RMRS/2025-26630	Date: 01.12.2025
Notice inviting bid	
Bids for various items of subject matters of procurement are invited from interested bidders upto 23.12.2025, 10.00 AM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal http://sppp.raajasthan.gov.in of the state.	
UBN NO. 1.MCU2526GLRC00307. The approximate value of the procurement is Rs. 20 lakh.	
UBN NO. 2.MCU2526GLRC00308. The approximate value of the procurement is Rs. 30 lakh.	
Member Secretary	
Rajasthan Medicare Relief Society	
DIPR/C/17962/2025	

 कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन स्वा.अभि.विभाग, वृत्त प्रतापगढ	
E-Mail: secircle_pra.phed@rajasthan.gov.in	
क्रमांक- अअ/प्रताप/निविदा/2025-26/2262-2267	दिनांक-02.12.2025
ई-निविदा सूचना	
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नहस्ताक्षरकों द्वारा सक्षम श्रेणी में मान्यता प्राप्त पंजीकृत संबद्धको से जिला प्रतापगढ के कार्या हेतु ऑनलाईन निविदा सं. 09-10/2025-26 आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित अन्य सभी विस्तृत विवरण मग निम्न लिंकियों के http://eproc.raajasthan.gov.in, www.sppp.raj.nic.in पर भी देखे जा सकते हैं।	
UBN No. As follows- NIT-09-PHE2526WSOB09300, NIT-10-PHE2526WSRC09301	
(शिवदयाल मीना) अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग वृत्त-प्रतापगढ (राज.)	
DIPR/C/17987/2025	

 राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर	
क्रमांक-वि.सं.12/Exam/Inspector(G&B)/RPSC/EP-1/2025-26	दिनांक- 08.12.2025
आयोग द्वारा अवरजाना एवं बीयन्स विभाग निगम के लिए राजस्थान सरकारका तथा अजमेर नरेशिक और कसरना नरेशिक (रखतन) सेवा निगम, 1958 के अन्तर्गत निरदेशक, कसरना एवं बीयन्स (Inspector of Factories & Boilers) के 12 पदों तथा निरदेशक, कसरना (रखतन) (Inspector of Factories & Boilers) के 01 पद पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वैशेषिक योग्यता आदर्श प्रक्रिया व अन्य विस्तृत जानकारी के लिए अप्रत्यक्ष उक्त पदों हेतु आयोग की वेबसाईट पर अथवा विस्तृत विज्ञापन कर अवलोकन करें। उक्त पदों हेतु आयु सीमा, आवेदन अर्जाव व अन्य विवरण निम्नानुसार-	
आयु सीमा	दिनांक 01.01.2027 को न्यूनतम 23 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए।
अवकाश तिथि	दिनांक 14.12.2025 से दिनांक 12.01.2026 तक। यत्ति 12.00 बजे तक
परीक्षा का स्थान व माह	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध

राजस्थान हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की फिर मिली धमकी

इससे पूर्व गत 31 अक्टूबर को भी यहां बम ब्लास्ट की धमकी का ई-मेल मिल चुका है, हालांकि राहत की बात है कि तलाशी में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन को एक बार फिर धमकी मिली है। बीते चार दिन में यह दूसरा मौका है, जब हाईकोर्ट में बम धमाका करने की धमकी दी गई है। इससे पूर्व गत 31 अक्टूबर को भी यहां बम ब्लास्ट की धमकी का मेल मिल चुका है, हालांकि राहत की बात है कि तलाशी में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भेजे गए इस मेल में हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की बात कही गई है। ई-मेल की जानकारी मिलने ही उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई और पूरे हाईकोर्ट परिसर को खाली करवाया गया। वहीं न्यायाधीशों ने भी प्रकरणों की सुनवाई बीच में बंद कर दी।

हाईकोर्ट चौकी प्रभारी सुमेर सिंह ने बताया कि बम की सूचना मिलते ही पुलिस के बम निरोधक दस्ते और डॉंग स्क्वाड की ओर से पूरे हाईकोर्ट परिसर के चप्पे-चप्पे की जांच की गई। वहीं हाईकोर्ट परिसर से न्यायिक कर्मचारियों, अधिकारताओं व पक्षकारों को बाहर निकाला गया। डीसीपी साठय राजर्षि राज ने बताया कि बदमाश



राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन में मुख्यमंत्री ने सुनीं लोगों की समस्याएं।

वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। वीपीएन के कई प्रकार होते हैं। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी और मैन पावर है। उसका इस्तेमाल करके आरोपियों को जल्दी ही ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि जल्दी ही कुछ कामयाबी मिलेगी।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने कहा है कि हाईकोर्ट परिसर

की सुरक्षा को लेकर मजक की सी स्थिति बन गई है। बीते डेढ़ माह में हाईकोर्ट को तीन बार बम से उड़ाने के मेल मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जांच एजेंसियां अभी तक यह तक मालूम नहीं कर पाई हैं कि ई-मेल कहां से आया है। हर बार मेल मिलने के बाद मुकदमों की सुनवाई बीच में बंद कर दी जाती है और कोर्ट

■ **बम की धमकी के बाद सोमवार को पूरे हाईकोर्ट परिसर को खाली करवाया गया, न्यायाधीशों ने भी प्रकरणों की सुनवाई बीच में बंद की, जो कि 2 बजे बाद पुनः शुरू हुई**

परिसर खाली करा लिया जाता है। जिससे एक और भय का माहौल पैदा हो गया है, वहीं मुकदमों की सुनवाई भी प्रभावित होती है। हाईकोर्ट के अधिकारता रामप्रताप सैनी ने कहा कि डढ़ माह में ही तीसरी बार हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलना गंभीर है। ऐसे में हाईकोर्ट प्रशासन व पुलिस प्रशासन को इन दोनों ईमेल की जांच करवानी चाहिए कि ये कहां से आ रहे हैं।

पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों की ओर से कोर्ट परिसर की पूरी तलाशी लेने के बाद क्लीन चिट दी गई। इसके बाद हाईकोर्ट में दोपहर दो बजे बाद से केंसों की सुनवाई शुरू हुई। हालांकि सुबह बम की धमकी मिलने के चलते अदालतों में सुनवाई नहीं हुई और हजारों प्रकरण प्रभावित हुए।

मुख्यमंत्री ने सुनीं राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन में लोगों की समस्याएं

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमावर को सचिवालय में दौरा करते हुए अचानक राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन सेंटर 181 पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने दो कॉलर्स नवलगढ़ (द्युन्द्युर्ग) के सुधीर और

■ **181 पर आ रही समस्याओं की बढ़ाई जाए मॉनिटरिंग : भजनलाल शर्मा**



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन 181 का औचक निरीक्षण किया और परिवारियों की समस्याएं सुनीं।

शिकायतकर्ता नेमीचंद निवासी गोकलपुर गांव, वार्ड नंबर 29 (कोटपूतली-बहरोड़) ने मुख्यमंत्री को फोन पर बताया कि गोकलपुर गांव में वार्ड नंबर 29 में नाले की सफाई नहीं होने के कारण गंदा पानी निकलकर सड़क पर भरा हुआ है। जिससे आवागमन में लोगों को समस्या आ रही है तथा बीमारी का खतरा भी बना हुआ है। उन्होंने इस नाले की जल्द से जल्द सफाई कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री के आदेश पर संबंधित कलक्टर ने नाले की तुरंत सफाई करवाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 181 हैल्पलाइन के माध्यम से आमजन घर बैठे अपनी समस्या दर्ज करवाकर उसका शीघ्र समाधान प्राप्त कर रहे हैं। संपर्क पोर्टल पर आ रही समस्याओं की अधिक से अधिक मॉनिटरिंग हो जिससे परिवादी की समस्या का समयबद्ध निस्तारण हो सके तथा उसे राहत मिले। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रणाली को समझने एवं उसे और बेहतर बनाने के लिए स्वयं ही शिकायतकर्ताओं का कॉल अटेंड किया तथा उनकी समस्याओं का समाधान किया।

आधुनिक और भारतीय शिक्षा के समन्वय का मार्ग प्रशस्त करेगा शिक्षा बोर्ड : डॉ. एन.पी. सिंह

प्रयागराज। एएमए कन्वेंशन सेंटर प्रयागराज में आयोजित संगोष्ठी में भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. एन. पी. सिंह ने कहा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य स्वदेशी शिक्षा पद्धति को पुनर्जीवित करते हुए आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय स्थापित करना है। आज देश को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो विद्यार्थियों में आत्मगौरव, भारतीयता, नैतिकता, नेतृत्व क्षमता और वैश्विक दृष्टि दोनों का विकास कर सके। इसी उद्देश्य को केंद्र में रखकर भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है, जिसे राष्ट्रीय और राज्य बोर्डों के समकक्ष मान्यता प्राप्त है।

डॉ. सिंह ने बताया कि बोर्ड के पाठ्यक्रम में वेद, उपनिषद, गीता, जैन और बौद्ध दर्शन, भारतीय शूद्रवीरों की कथाएँ, संवैधानिक मूल्य, गुरुकुल परंपरा और आधुनिक विज्ञान-प्रौद्योगिकी को संतुलित रूप से जोड़ा गया है। पाठ्यक्रम



भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. एन. पी. सिंह ने प्रयागराज में संगोष्ठी को संबोधित किया।

में भारत के लगभग 120 महान नायकों की जीवनगाथाओं को भी शामिल किया है। यह शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को केवल नौकरी योग्य नहीं बल्कि रोजगार सृजन में सक्षम बनाएगी। बोर्ड का पाठ्यक्रम यूपीएससी, नेट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप की विकसित किया गया है। यह बोर्ड के समकक्ष है, यह कक्षा 9 से 12 तक की स्कूलों को मान्यता देती है। कक्षा 1 से 8 तक के मान्यता प्राप्त विद्यालय भारतीय शिक्षा बोर्ड से मान्यता ले सकते हैं।

विशिष्ट अतिथियों में संयुक्त शिक्षा निदेशक राम नारायण विश्वकर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक पी. एन. सिंह, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संयुक्त कुल सचिव मेजर डॉ. हर्ष कुमार उपस्थित रहे। भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी भगवान सिंह भी कार्यक्रम में सहभागी रहे। कार्यक्रम का संचालन वृज मोहन ने किया।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केन्द्र खोलेगी भजनलाल सरकार

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना करेगी, ताकि ग्रामीण युवाओं को डिजिटल शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और करियर परामर्श जैसी सुविधाएं मिल सकें। यह पहल राज्य सरकार के पिछले 2 वर्षों के समर्पित प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें विकास, शिक्षा और युवा सशक्तीकरण पर विशेष जोर दिया गया है।

ज्ञात रहे कि अटल ज्ञान केन्द्रों में ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर और इंटरनेट, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ी पुस्तकें, करियर परामर्श और क्षमता निर्माण

- **प्रथम चरण में 3000 से अधिक आबादी वाली 1274 पंचायतें चिन्हित**
- **इन जगहों पर ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर और इंटरनेट, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, करियर परामर्श और क्षमता निर्माण कार्यक्रम होंगे**

कार्यक्रमों की सुविधा होगी। पहले चरण में 3000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत मुख्यालयों को प्राथमिकता दी गई है। अब तक 1274 केंद्रों को चिन्हित कर इनके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इस चरण के बाद प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा।

पिछले दो वर्षों में भजनलाल सरकार

ने युवा प्रोत्साहन, ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं। अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना इसी दिशा में एक और मील का पत्थर है, जो ग्रामीण युवाओं को शहरों के समकक्ष अवसर प्रदान करेगा। इन केंद्रों से न केवल शिक्षा का प्रसार होगा, बल्कि

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। अटल ज्ञान केंद्रों को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार का सहयोग प्राप्त हुआ है। पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत राजस्थान के लिए 1047 पंचायत लर्निंग सेंटर (पीएलसी) की स्वीकृति प्रदान की गई है। करीब 232 करोड़ रुपये से अधिक की यह सहायता केंद्रों के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना, डिजिटल सुविधाएं और प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाएगी। इस सहायता से केंद्रों में उन्नत कंप्यूटर लैब, ई-लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे।

‘नई श्रम संहिताएं श्रमिक कल्याण हितैषी’

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नई श्रम संहिताएं श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव हैं। इनके माध्यम से मजदूर और कारोबार के हितों की सुरक्षा होगी और देश-प्रदेश के अनुकूल औद्योगिक वातावरण में वृद्धि होगी। उन्होंने केन्द्र सरकार की मंशानुसार नई श्रम संहिताओं के प्रदेश में समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देशित किया। शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में नवीन श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई श्रम संहिताओं के अनुसार सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र जारी करने की अनिवार्यता की गई है।

निवेशकों की मांग पर एन.सी.आर. में औद्योगिक भूमि उपलब्ध कराएगा रीको

उद्योगों की स्थापना के लिए बीडा 209 हैक्टेयर भूमि रीको को आवंटित करेगा

जयपुर (कासं)। “राईजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024” के उपरांत विभिन्न उद्यमियों और औद्योगिक ग्रुप्स ने एनसीआर क्षेत्र में अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की मंशा जाहिर थी। उनकी इस मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने अविलंब भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके उपरांत बीडा द्वारा लगभग 209 हैक्टेयर भूमि रीको को उपलब्ध कराई जायेगी। इस भूमि आवंटन से एक ओर औद्योगिक प्रतिष्ठानों को शीघ्रता से भूमि उपलब्ध करायी जा सकेगी, दूसरी ओर बीडा को लगभग 110 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति भी होगी, जिसका उपयोग बीडा द्वारा क्षेत्र के विकास एवं आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में किया जा सकेगा। राज्य सरकार के इस कदम से राज्य में औद्योगिक माहौल विकसित करने

■ **रीको द्वारा जयपुर के जगतपुरा स्थित अपैरल पार्क में भी किया जाएगा औद्योगिक विकास**

और 350 करोड़ बिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होगी। औद्योगिक विकास को गति देने और निवेशकों को विश्वास मजबूत करने के उद्देश्य से रीको और जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपैरल पार्क, जगतपुरा से संबंधित लंबे समय से चल रही भूमि समस्या का सफलतापूर्वक समाधान कर लिया है। रीको द्वारा मुख्य महल रोड पर अपैरल पार्क की स्थापना वर्ष 2014 में लगभग 122 एकड़ पर की गई थी, जिसमें

टैक्सटाइल एवं अपैरल उत्पादों के लिये ही औद्योगिक भूमि का आवंटन किया गया था। खातेदारों द्वारा लंबे समय से उन्हें 25 प्रतिशत विकसित भूमि दिए जाने की मांग की जा रही थी। जेडीए के पास खातेदारों की मांग अनुसार विकसित भूमि दिए जाने हेतु पर्याप्त भूमि की अनुपलब्धता देखते हुए रीको से अतिरिक्त भूमि की मांग की गई थी।

रीको ने एक एमओयू जेडीए के साथ निष्पादित कर मुख्य 160 फीट रोड पर 4.57 हैक्टेयर भूमि खातेदारों से विवाद का समाधान करने के उद्देश्य से जेडीए को हस्तांतरित करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है। जेडीए इस भूमि का उपयोग खातेदारों को दी जाने वाली विकसित वाणिज्यिक भूमि के रूप में कर सकेगा, जिसके लिये जेडीए ने आवश्यक कार्यवाही भी प्रारंभ

कर दी है। इस कदम से ना सिर्फ विभिन्न गतिविधियों के लिये भूमि की उपलब्धता हो सकेगी, बल्कि जयपुर के प्रमुख महल रोड पर अन्य आर्थिक गतिविधियों जैसे सेवा क्षेत्र इत्यादि के लिये भी भूमि उपलब्ध हो सकेगी। गारमेंट एवं अपैरल सेक्टर में मुख्य नियोजन महिलाओं का होता है, इसलिए यहां महिलाओं के लिये भी रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकेंगे और ग्लोबल कैपेबिलिटी क्षेत्र, को-वर्किंग सेंटर, वाणिज्यिक परिसर, होटल आदि के निर्माण से पछे लिखे युवाओं को भी आने वाले समय में उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार के नए अवसर विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त हो सकेंगे। इस कदम से उन कार्तकारों ने भी राहत की सांस ली है जो लंबे समय से अपनी भूमि के एवज में विकसित भूमि की मांग कर रहे थे।

राजीविका ग्रामीण उद्यिमता का सशक्त मॉडल : मुख्य सचिव



मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों का सोमवार को अवलोकन किया।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सोमवार को सांगानेर के टीकरिया स्थित राजीविका विकास क्लस्टर लेवल फेडरेशन पहुंचे। जहां उन्होंने ब्लू प्रिंटीर एवं बगर प्रिंट से जुड़ी लखपति दीदियों से संवाद कर उनकी आजीविका गतिविधियों के अनुभव जाने।

मुख्य सचिव ने आवेगस्त किया कि राजस्थान की स्वयं सहायता समूहों

की इन प्रेरणादायक कहानियों को प्रधानमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्य सचिव ने महिलाओं द्वारा निर्मित विविध उत्पादों की विशेष प्रशंसा भी की। साथ ही सेनेटरी नेपकिन यूनिट का अवलोकन किया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा ने कहा कि ग्रामीण महिलाएँ

अपने कौशल एवं परिश्रम से पूर्णतः स्वतंत्र एवं आत्मविश्वासी बन रही हैं। राजीविका प्लेटफॉर्म ने महिलाओं में उद्यिमता को मजबूत आधार प्रदान किया है। राजीविका की महिलाएं अपने उत्पाद सीधे ही बड़ी कंपनियों को बेच सकेगी उन्होंने आश्वासन दिया ‘बायर सेक्टर मीट’ को और व्यापक स्तर पर बढ़ाया जाएगा।

सांगानेर में पहला राजकीय विधि महाविद्यालय प्रारंभ

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार “आपणो अण्णो राजस्थान” के संकल्प की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। विधि के क्षेत्र में भविष्य बनाने की चाहत रखने वाले युवाओं को राज्य सरकार ने एक नवीन सौगात दी है। सांगानेर क्षेत्र में जयपुर जिले का प्रथम राजकीय विधि महाविद्यालय प्रारंभ किया गया है।

इस महाविद्यालय में तीन वर्षीय एल.एल.बी. पाठ्यक्रम का संचालन किया जाएगा, जिसकी 120 सीटों पर प्रवेश के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति प्राप्त हो चुकी है तथा प्रवेश प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। राज्य सरकार द्वारा विधि महाविद्यालय के भवन हेतु 4.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है तथा शीघ्र ही भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण कार्य के लिए टेण्डर जारी कर दिये जायेंगे। स्थाई भवन निर्मित होने तक अस्थाई तौर पर महाविद्यालय का संचालन शहीद पुनीत नाथ दत्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में किया जा रहा है।

■ **विधि महाविद्यालय के भवन के लिए 4.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए**

विधि महाविद्यालय के लिए राज्य सरकार ने 19 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इनमें सहायक आचार्य के सात, कनिष्ठ सहायक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के दो-दो तथा प्राचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षक, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सूचना सहायक, वरिष्ठ सहायक एवं बुक लिफ्टर के एक-एक पद शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार और युवाओं को प्रतिस्पर्धी युग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए स्थापित नवीन विधि महाविद्यालय युवाओं के लिए एक सशक्त मंच साबित होगा। इससे युवा कानूनी शिक्षा ग्रहण कर न्याय और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कलखीन योगदान दे सकेंगे।

जयपुर। राजधानी जयपुर के बजाज नगर स्थित एजी कॉलोनी में रविवार की देर शाम को लेपर्ड का मूवमेंट होता देख स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। इसके बाद लोगों ने वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सोमवार को सर्च ऑपरेशन चलाया, परंतु टीम

■ **वन्य अधिकारियों का मानना है कि भोजन-पानी की तलाश में लेपर्ड आबादी क्षेत्र में पहुंचा होगा**

को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। रैज ऑफिसर जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि सोशल मीडिया से यह विडियो मिलने पर वन विभाग टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि अभी तक लेपर्ड नहीं मिला है।

जानकारी के अनुसार लाल बहादुर कॉलोनी में रविवार को बजाज नगर एक्लेव, सरस्वती कॉलोनी और अनिता कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज में लेपर्ड घूमता हुआ दिखाई दिया। जहां लेपर्ड की कई घंटों में घुसा,कभी गलियों से निकला। फुटेज वायरल होते ही कॉलोनियों में दहशत फैल गई। लोग सतर्क हो गए और वेलफेयर सोसायटी ने चेतावनी जारी कर दी। वन विभाग को रैस्पूड टीम मौके पर पहुंची। लेकिन लेपर्ड हाथ नहीं आया। रेंज ऑफिसर



जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि यह एक वर्ष से भी कम उम्र का शावक है और अब मॉनिटरिंग टीमें लगातार निगरानी कर रही है। आशंका है कि शावक स्टेशन के पास नाले से होते हुए वापस जंगल की ओर चला गया। उसके जेएलएन रोड पार कर शिक्षा संकुल की ओर से आने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि लंबे समय से एएमएआईटी में भी लेपर्ड की मूवमेंट है।

अनिता कॉलोनी निवासी अरुण कुलश्रेष्ठ ने बताया कि सुबह करीब 5 बजे बजाज नगर एक्लेव कॉलोनी में मॉनिंग वॉक कर रही एक महिला को लेपर्ड का एक शावक दिखा। उसे देखते ही महिला ने शोर मचाया। जिस पर शावक वहां से भाग गया। इसकी जानकारी आसपास की कॉलोनियों में तेजी से फैल गई। कुछ देर बाद यह शावक सरस्वती कॉलोनी से होता हुआ अनिता कॉलोनी पहुंचा। यहां दो घंटों में घुसा, जिसका मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। चीफ वाइल्डलाइफ

वार्डन केसी अरुण प्रसाद की ओर से गठित क्विक रिसॉन्स टीम और रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत की टीम मौके पर लगातार निगरानी कर रही है। टीम आधुनिक तकनीक, ट्रैक्स और स्थानीय इन्फुट की मदद से लेपर्ड के मूवमेंट को ट्रैक कर रही है। जानकारी के अनुसार यह पूरा जोन झालाना लेपर्ड सफारी की परिधि से जुड़ा हुआ है। जहां पर करीब 40 से अधिक लेपर्ड रहवास करते हैं। जहां से भोजन और पानी की तलाश में लेपर्ड आवासीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में शहर के कई हिस्सों में लेपर्ड की मूवमेंट की घटनाएं बढ़ने से वन विभाग भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। गौरतलब है कि राजधानी जयपुर में पिछले एक महीने में शहर में कई बार लेपर्ड के रिहायशी इलाकों में आने की घटना हो रही है। इस दौरान लेपर्ड सिविल लाइंस, गुर्जर की घाटी, विद्याधर नगर, शास्त्री नगर, चांदपोल, मोती डूंगरी इलाकों में देखे गए हैं।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-1720 विकल्प स्वीकृति चाहने वालों आम सूचना दिनांक:-8.12.20

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा योजना श्रीरामकुण्डगुरुप ए आवासों का भूखण्ड/आवास संख्या 1009 श्री राज नारायण पुत्र श्री मोतीलाल प्रजापति को आनन्द/नीलामा प्रदिनांक 18.12.2001 के द्वारा आवंटन किया गया था। अतः उक्त भूखण्ड की विकल्प स्वीकृति जय मुखाराम पुत्र श्री त्रिलोक चंद महावर पुत्र श्री खूब चन्द महावर द्वारा कोटा विकास प्राधिकरण कोटा से चोही जा रही है।

अतः जरूरी आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम विकल्प स्वीकृति देने में किसी को भी कोई पेशाज हो तो विवाचित जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा मिनाव गुरजेर के पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 1009 योजना श्रीरामकुण्डगुरुप ए आवासों की विकल्प स्वीकृति श्री राज नारायण पुत्र श्री मोतीलाल प्रजापति जय मुखाराम पुत्र श्री त्रिलोक चंद महावर पुत्र श्री खूब चन्द के नाम स्वीकृति जारी कर दी जायेगी।

उपयुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

अब तक 8738 प्रवासी राजस्थानियों ने राजस्थानी दिवस आयोजन में पंजीकरण कराया

योगदान को सम्मानित करने के लिए पहली बार प्रवासी राजस्थानी दिवस का भव्य आयोजन भी आगामी 10 दिसम्बर को किया जा रहा है। देश-विदेश से अब तक 8,738 प्रवासी

राजस्थान फाउंडेशन अपने चैप्टर्स के माध्यम से देश-विदेश में तीज, गणगौर, दिवाली, होली, मकर संक्रांति आदि धार्मिक व सांस्कृतिक त्योहारों का ऑनलाइन और ऑफलाइन आयोजन करेगा, जिनमें एन.आर.आर. एसोसिएशन भी भागीदार होंगे।

राजस्थानियों ने आयोजन में शामिल होने के लिए अपना पंजीकरण कराया है। विज्ञान, कला, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, खेल, साहित्य और सामाजिक सेवा सहित, विभिन्न श्रेणियों में प्रवासी राजस्थानियों के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रवासी राजस्थानी सम्मान अवार्ड्स समारोह का आयोजन किया जाएगा।

■ मानें न मानें, भारत की सबको हवाई यात्रा उपलब्ध कराने की महत्त्वकांक्षा काफी कमज़ोर नींव पर आधारित है।

प्रशिक्षण की व्यवस्था भी तेजी से बढ़ते बेड़े के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई है, जिससे कमजोरियाँ पैदा होती हैं और जरा-सी स्टाफिंग या शेड्यूलिंग की दिक्कत आते ही सामने आ जाती हैं। इंडिगो की घटना ने यह साफ कर दिया कि क्षमता उपयोग को ज़रूरत से ज्यादा बढ़ाने के प्रयास कभी-कभी पूरे सिस्टम

“नेहरू कट्टरता से लिखते हैं कि जो भी ‘वन्दे मातरम्’ के शब्दों को देवी से संबंधित समझे, वह बेतुका है,” हालांकि सितंबर के पत्र में इस संदर्भ में नेहरू ने यह कहा था कि गीत के शब्दों का देवी से कोई संबंध समझना बेतुका है, न कि ऐसा समझने वाला व्यक्ति।

पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सोमवार दोपहर में बैठक हुई थी। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और संसदीय कार्यमंत्ररंजना जोगाराम पटेल शामिल हुए। तीनों की

■ वे पूर्व आईएस
अधिकारी हैं तथा
मुख्यमंत्री की
अध्यक्षता में
टीकाराम जूली व
जोगाराम पटेल ने
उनके नाम का चयन
किया।

कमेटी ने सुनील शर्मा के नाम की सिफारिश राज्यपाल से की। इसके बाद राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए।

प्रियंका गांधी ने कहा, “मैं गुरुदेव (रवीन्द्र नाथ टैगोर) के पत्र का एक अंश साझा करती हूँ, जिसमें वे कहते हैं कि जिन दो पदों का हमेशा गायन होता रहा है, वे इतने अर्थपूर्ण हैं कि उन्हें बाकी कविता से

अलग करने में उन्हें कोई समस्या नहीं हुई। आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी यही दो पद गए जिते थे, और उन हज़ारों शहीदों का सम्मान करने के लिए, जिन्होंने अपनी जानें त्यागवारी की। इसलिए इन्हें वैसे ही गाना जाना उचित है। उन्होंने यह भी कहा कि बाद में जो अन्य पद जोड़े गए थे, उन्हें सांप्रदायिक रूप में देखा जा सकता है और उस समय के माहौल में उनका उपयोग उचित नहीं होता।

प्रियंका ने आगे बताया कि 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्यसमिति ने एक प्रस्ताव पारित करके वंदे मातरम् को राष्ट्रीय गीत घोषित किया था।

बजे 6ई 1073 फ्लाइट लेकर फुकेट (थाईलैंड) लैंकन गए थे। गोवा पुलिस ने रेस्टोरेरें घर भागल गोवाल और सोम पुलिस के दिल्ली के घर टीन भेजे लेकिन वो घर पर नहीं मिले। इनके घर पर गोवा पुलिस ने नोटिस चपका किया है, गोवा पुलिस की किस्केट 7 दिंसंबर को दोनों के खिलाफ एलओसी जारी कर गई थी, जिससे दोनों देश छोड़कर न भाग सकें लेकिन दोनों पहले ही फरार हो चुके हैं। गोवा पुलिस ने सीबीआई की मदद से इंटरपोल के जरिए इनकी लोकेशन ट्रे करके के इल्टीमेटियम शुरू कर दी है।

स्लॉट आवंटन और इसके व्यापक निजीकरण रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। एनडीए के भीतर से यह अप्रत्याशित विद्रोह और भी जटिल हो गया है, क्योंकि सहयोगी जरूरी जवाबदेही और जनता के लिए तत्काल राहत की मांग कर रहे हैं।

एयरलाइन संचालन में समस्याएं जारी हैं, राजनीतिक परिणाम और भी गहरे हो रहे हैं। इस वर्तमान संकट में, सरकार पर दबाव विपक्ष से नहीं, बल्कि इसके अपने सहयोगियों से आ रहा है, जिससे विमानन संकट पूर्ण राजनीतिक सिरदर्द में बदल गया है।

परीक्षा पेपर लीक मामले का खुलासा होने के बाद से फरार चल रहा था। वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 के पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद बांसवाड़ा जिले के राजतलाब थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। राजस्थान एसओजी इसका

जांच कर रही है। आरोपी जबराम बालोतरा जिले के कालवा गांव का निवासी है और वह बाड़मेर जिले के रामजी का गोल गांव के सरकारी स्कूल में अध्यापक पद पर तैनात है। उसकी गिरफ्तारी पर एसओजी ने 50 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की थी।

सुमेल्लिय मंडिय, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस परमारवा हाऊस, छपति सिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-जयेश शर्मा आ.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकारे कार्यालय कुम्भना हाऊस, हनुमान हथ्या, बीकारे नं. 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आर्य मैन रोड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राधुदत पवन, नं.150, रीवा नका के पार्क, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665 जालोर कार्यालय - जी 1/63, इन्स्टीट्यूट एरिया, फेस प्रथम जालोरा फोन:226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डनसिटी कार्यालय - जी -1-1-201, रीवा औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरु कार्यालय : एम-150, रीवा औद्योगिक क्षेत्र, चूरु, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908